

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1938 (श0)

(सं० पटना ४९१) पटना, मंगलवार, १४ जून २०१६

सं0 **07 / सह. / आई.सी.डी.पी.—13 / 2014—379** सहकारिता विभाग

संकल्प 29 जनवरी 2016

विषय :— औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया (पं. चंपारण), दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्ति के आधार पर सम्पोषित ''समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई॰सी॰ डी॰पी॰)'' के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा परियोजना अविध तक राज्य अनुश्रवण कोषांग, आई॰सी॰डी॰पी॰ का कार्यरत पदबल के साथ अविध विस्तार की स्वीकृति।

- 1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के रा.स.वि.नि. : 3–6 (30) 2012—आईसीडीपी (129) (A140005), 3–6 (24) 2012—आईसीडीपी (132) (A140008), 3–6 (22) 2010—आईसीडीपी (131) (A140007), 3–6 (23) 2010—आईसीडीपी (133) (A140009) एवं 3–6 (25) 2010—आईसीडीपी (130) (A140006) दिनांक 24. 09.2014 के अनुसार क्रमशः औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) कार्यान्वयन की स्वीकृति के उपरांत राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19.01.2016 के मद संख्या—15 द्वारा उपरोक्त जिलों में वर्ष 2015—16 से 2019—20 (पाँच वार्षिक चरण) में परियोजना कार्यान्वयन की स्वीकृति संसूचित की जाती है।
- 2. निबंधक, सहयोग सिमितियाँ, बिहार, पटना को इन परियोजनाओं के लिए (Nodal) पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है। परियोजना राशि की निकासी सिचवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष लि॰ सिचवालय शाखा (विकास भवन) के माध्यम से उक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यालय के लिये प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे एवं परियोजना राशि को संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष लि॰ के सिचवालय शाखा, पटना में खोले गये विशेष बचत खाते में आहरण के तुरंत बाद हस्तांतरित कर देगें एवं इसका उपयोग परियोजना अविध में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3. परियोजना कार्यान्वयन के लिये औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया एवं पूर्णियाँ जिले के लिये केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि॰, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया एवं पूर्णियाँ तथा दरभंगा जिला के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी॰आई॰ए॰) घोषित किया जाता है।

- 4. राज्य में संचालित समेकित सहकारी विकास परियोजना के अनुश्रवण हेतु निबंधक, सहेयाग समितियाँ, बिहार, पटना के अधीन पूर्व से गठित राज्य अनुश्रवण कोषांग, समेकित सहकारी विकास परियोजना (कार्यरत पदबल सहित) को इन परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण हेतु इन परियोजनाओं की अवधि तक विस्तारित किया जाता है।
- 5. (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के स्वीकृति पत्रांकों एवं योजना प्राधिकृत समिति तथा राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया (पं चंपारण), दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के लिए स्वीकृत परियोजना की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है :—

(राशि लाख रुपये में)

		योजित् योजना प्र		,	·	
परियोजना	राशि राज्य सरव	गर को शत–प्रति	राज्य योजना			
जिला का		पर प्र	ग्रप्त		से राज्यांश	कुल लागत
नाम	ऋण	अनु	दान	कुल राशि	अनुदान राशि	राशि
गान		एल。डी。 /	पी•आई•टी•			
		यू.डी.				
1	2	3	4	5	6	7
औरंगाबाद	8279.28000	2564.76000	277.25000	11121.29000	277.25000	11398.54000
बेगुसराय	8279.28000 4390.33250	2564.76000 1417.29750	277.25000 224.46700	11121.29000 6032.09700	277.25000 224.46800	11398.54000 6256.56500
_						
बेगुसराय बेतिया दरभंगा	4390.33250	1417.29750	224.46700	6032.09700	224.46800	6256.56500
बेगुसराय बेतिया	4390.33250 5924.95125	1417.29750 1926.38375	224.46700 270.39500	6032.09700 8121.73000	224.46800 270.39500	6256.56500 8392.12500

परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्राप्त होनेवाली कुल राशि में से एन॰सी॰डी॰सी॰ अंश राशि की प्रतिपूर्ति (Reimburesement) एन॰सी॰डी॰सी॰, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी।

- (ख) दिनांक 21.06.2012 को सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में राज्य सरकार प्राथमिक स्तर की समितियों को मजबूत बनाने तथा समेकित सहकारी विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के राशि विमुक्ति पैर्टन (Funding Pattern) में समरुपता लाने के लिए निगम से प्राप्त होने वाली ऋण एवं एल.डी. / यू.डी. अनुदान राशि को चक्रीय पूंजी (Revolving Capital) एवं अनुदान (एल.डी. / यू.डी. के अतिरिक्त एवं एल.डी. / यू.डी.) के रुप में विमुक्त करेगी।
- (ग) राज्य सरकार पाँचों जिलों के लिए निगम से ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली ₹ 28667.91875 लाख रूपये एवं एल.डी. / यू.डी. अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली ₹ 9203.72625 लाख रूपये को चक्रीय पूंजी एल.डी. / यू.डी. के अतिरिक्त अनुदान एवं एल.डी. / यू.डी. अनुदान के रूप में सिमितयों को उपलब्ध करायेगी, जो क्रमशः ₹ 18935.8225 लाख, ₹ 9732.09675 लाख तथा ₹ 9203.72575 लाख रूपये है। पी.आई.टी. अनुदान मद में निगम एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 1241.307 एवं ₹ 1241.308 लाख कुल ₹ 2482.615 लाख रूपये विमुक्त करेगी। अनुदान (एन.सी.डी.सी. से प्राप्त एल.डी. / यू.डी. सिहत) एवं चक्रीय पूंजी (Revolving Capital) का अनुपात 50:50 का रहेगा तथा पी.आई.टी. अनुदान देने की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी, जिसमें 50% निगम एवं 50% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। राज्य सरकार द्वारा निगम के मार्गदर्शन के विरुद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अविध के लिए विमुक्त की जाने वाली राशि की जिलावार विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

				(शारा लाख	V 19 19		
परियोजना जिला का नाम		্ত্ৰভা _• /	पूरी अवधि के ति गि.डी.सी. अंश राधि अनुदान एल.डी./	राज्य योजना से राज्यांश अनुदान राशि	कुल लागत राशि		
		यू.डी. के अतिरिक्त	यू.डी.			VIIXI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.			•			,	, ,
औरंगाबाद	5422.0200	2857.26000	2564.76000	277.250	11121.290	277.250	11398.540
बेगुसराय	2903.8150	1486.51800	1417.29700	224.467	6032.097	224.468	6256.565
बेतिया	3925.6675	1999.28375	1926.38375	270.395	8121.730	270.395	8392.125
दरभंगा	4050.7000	2025.35000	2025.35000	249.390	8350.790	249.390	8600.180
पूर्णियाँ	2633.6200	1363.68500	1269.93500	219.805	5487.045	219.805	5706.850
कुल योग :	18935.8225	9732.09675	9203.72575	1241.307	39112.952	1241.308	40354.260

- (घ) परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य एवं व्यवसाय विकास हेतु समितियों को दी जाने वाली संपूर्ण राशि चक्रीय पूंजी मद में ₹ 18935.8225 लाख, एल。डी。 / यू.डी。 के अतिरिक्त अनुदान मद में ₹ 9732.09675 लाख कुल ₹ 28667.91925 लाख रुपये की प्रतिपूर्त्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को "ऋण मद" में तथा एल。डी。 / यू.डी。 अनुदान मद में ₹ 9203.72575 लाख तथा स्थापना आदि व्ययों हेतु अनुदान मद में ₹ 1241.307 लाख कुल ₹ 10445.03275 लाख रुपये की प्रतिपूर्त्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को "अनुदान मद" में की जायेगी। स्थापना आदि व्यय हेतु राज्यांश अनुदान मद में ₹ 1241.308 लाख रुपये राज्य सरकार अपने संशाधनों से उपलब्ध करायेगी।
- (ङ) औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के लिए चरणवार / वर्षवार स्वीकृत वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है :-

समेकित सहकारी विकास परियोजना, औरंगाबाद

(राशि लाख रुपये में)

(सारा लाख रुपय म)							'/
परियोजना जिला / परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी / वर्ष	कार्यान्वयन ^१	रकार द्वारा नि एजेंसी को परि मुक्त की जाने	राज्य योजना से राज्यांश	कुल लागत			
	चक्रीय		अनुदान		कुल		राशि
औरंगाबाद केन्द्रीय	पूंजी	एल,डी. /	एल.डी./	पी आई टी -	Ü	अनुदान	रा।रा
सहकारी अधिकोष लि.,	ø	यू.डी. के अतिरिक्त	यू.डी.			राशि	
		अंतिरिक्त	~				
जिला – औरंगाबाद							
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण (2015-16)	1344.700	698.600	646.100	49.420	2738.820	49.420	2788.240
द्वितीय चरण (2016-17)	1748.250	906.625	841.625	51.835	3548.335	51.835	3600.170
तृतीय चरण (2017-18)	1606.100	850.550	755.550	60.030	3272.230	60.030	3332.260
चतुर्थ चरण (2018-19)	571.070	325.535	245.535	60.970	1203.110	60.970	1264.080
पंचम चरण (2019-20)	151.900	75.950	75.950	53.745	357.545	53.745	411.290
डी.पी.आर. शुल्क	=	-	-	1.250	1.250	1.250	2.500
कुल योग :	5422.020	2857.260	2564.760	277.250	11121.29 0	277.250	11398.540

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) शुल्क ₹ 2.50 लाख रुपये का भुगतान सलाहकार संस्था को पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 221 दिनांक 17.07.2013 द्वारा किया जा चुका है।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, बेगुसराय

(राशि लाख रुपये में)

	(सारा लोख रुपय म)						
परियोजना		ंद्वारा निगम के					
जिला / परियोजना	एजेंसी को	परियोजना कार्या	न्वयन हेतू पूरी	अवधि के लिए	विमुक्त की	राज्य	
कार्यान्वयन एजेंसी / वर्ष			एन.सी.डॉ.सी.		J	योजना से	
,	चक्रीय पूंजी	1111	अनुदान		क्रव	राज्यांश	कुल लागत
बेगुसराय केन्द्रीय	43/14 7011	एल ही /	एल.डी./	पी•आई•टी•	कुल		राशि
सहकारी अधिकोष लि.,		एल.डी. / यू.डी. क	यू.डी.	नाव्याञ्च ८।व		अनुदान	
		अतिरिक्त	70010			राशि	
जिला – बेगुसराय		-114114141					
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण (2015-16)	698.2200	380.7200	317.5000	44.6485	1441.0885	44.6485	1485.7370
द्वितीय चरण (2016-17)	1181.4450	592.2230	589.2220	44.6485	2407.5385	44.6485	2452.1870
तृतीय चरण (2017-18)	889.9500	446.4750	443.4750	44.6485	1824.5485	44.6485	1869.1970
चतुर्थ चरण (2018-19)	67.1000	33.5500	33.5500	44.6485	178.8485	44.6485	223.4970
पंचम चरण (2019-20)	67.1000	33.5500	33.5500	44.6480	178.8480	44.6490	223.4970
डी॰पी॰आर॰ शुल्क	-	-	-	1.2250	1.2250	1.2250	2.4500
कुल योग :	2903.8150	1486.5180	1417.2970	224.4670	6032.0970	224.4680	6256.5650

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) शुल्क ₹ 2.45 लाख रुपये का भुगतान सलाहकार संस्था को पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 129 दिनांक 24.03.2011 द्वारा किया जा चुका है।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, बेतिया (पं. चंपारण)

(राशि लाख रुपये में)

						T CHICA TO 14	- <i>1</i>
परियोजना		र द्वारा निगम के					
जिला / परियोजना	एजेंसी को पी	रेयोजना कार्यान्व	ायन हेतु पूरी अ	वधि के लिए वि	वेमुक्त की जाने	राज्य	
कार्यान्वयन एजेंसी / वर्ष		वाली ए	न सी डी सी. अं	श राशि	ŭ	योजना से	
	चक्रीय पूंजी		अनुदान		कुल	राज्यांश	कुल लागत राशि
बेतिया केन्द्रीय सहकारी	٠.	एল.ভী. /	एलं.डी. /	पी•आई•टी•	3	अनुदान	सारा
अधिकोष लि.,		एल.डी. / यू.डी. के अतिरिक्त	यू.डी.	,		राशि	
जिला – बेतिया		अतिरिक्त				VII VI	
191011 410141	•	2		_			0
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण (2015-16)	968.77000	504.88500	463.88500	73.89000	2011.43000	73.89000	2085.32000
द्वितीय चरण (2016-17)	984.44500	504.11000	480.33500	43.26000	2012.15000	43.26000	2055.41000
तृतीय चरण (2017-18)	740.57000	372.22250	368.34750	46.33000	1527.47000	46.33000	1573.80000
चत्तुर्थ चरण (2018-19)	656.62000	330.24750	326.37250	49.72000	1362.96000	49.72000	1412.68000
पंचम चरण (2019-20)	575.26250	287.81875	287.44375	55.97000	1206.49500	55.97000	1262.46500
44·1 4(-1 (201)-20)	0.01=0=0						
डी॰पी॰आर॰ शुल्क	-	-	-	1.22500	1.22500	1.22500	2.45000

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) शुल्क ₹ 2.45 लाख रुपये का भुगतान सलाहकार संस्था को पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 134 दिनांक 24.03.2011 द्वारा किया जा चुका है।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, दरभंगा

(राशि लाख रुपये में)

(तारा लाव ४४४ ग)							
परियोजना			मार्गदर्शन के वि				
जिला / परियोजना	एजेंसी को परि	रेयोजना कार्यान्व	ायन हेतु पूरी अ	वधि के लिए वि	वेमुक्त की जाने	राज्य	
कार्यान्वयन एजेंसी / वर्ष		वाली ए	न सी डो सी अं	श राशि	-	योजना से	
	चक्रीय पूंजी		अनुदान		कुल	राज्यांश	कुल लागत
जिला सहकारिता	6	एল.ভী. /	एल বী. /	पी आई टी .	5	अनुदान	राशि
पदाधिकारी,		एल.डी. / यू.डी. क अतिरिक्त	यू.डी.			राशि	
जिला – दरभंगा		आतारक्त					
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण (2015-16)	979.2500	489.6250	489.6250	53.1000	2011.6000	53.1000	2064.7000
द्वितीय चरण (2016-17)	1315.1000	657.5500	657.5500	46.6000	2676.8000	46.6000	2723.4000
तृतीय चरण (2017-18)	922.6500	461.3250	461.3250	46.6000	1891.9000	46.6000	1938.5000
चत्तुर्थ चरण (2018-19)	671.7500	335.8750	335.8750	46.7500	1390.2500	46.7500	1437.0000
पंचम चरण (2019-20)	161.9500	80.9750	80.9750	55.1000	379.0000	55.1000	434.1000
डी॰पी॰आर॰ शुल्क	-	-	-	1.2400	1.2400	1.2400	2.4800
कुल योग :	4050.7000	2025.3500	2025.3500	249.3900	8350.7900	249.3900	8600.1800

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) शुल्क ₹ 2.48 लाख रुपये का भुगतान सलाहकार संस्था को पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 130 दिनांक 24.03.2011 द्वारा किया जा चुका है।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, पूर्णियाँ

(राशि लाख रुपये में)

	(तार लाख रमप ग)						
परियोजना		ंद्वारा निगम के					
जिला / परियोजना	एजेंसी को परि	योजना कार्यान्व	यन हेतु पूरी अव	ाधि के लिए वि	मुक्त की जाने	राज्य	
कार्यान्वयन एजेंसी / वर्ष		वाली ए	न•सी•डी•सी• अंष	ग राशि	Ĭ	योजना से	कुल लागत
	चक्रीय पूंजी		अनुदान		कुल	राज्यांश	पुरा सारा राशि
पूर्णियाँ केन्द्रीय सहकारी	, and	एল,ঙী, /	एল বী 🗸	पी आई टी .	3	अनुदान	VIIVI
अधिकोष लि.,		एल.डी. / यू.डी. क अतिरिक्त	यू.डी.			राशि	
जिला – पूर्णियाँ		आतीरक्त					
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण (2015-16)	662.70500	343.47750	319.22750	39.92000	1365.33000	39.92000	1405.25000
द्वितीय चरण (2016-17)	1247.80750	650.40375	597.40375	44.83500	2540.45000	44.83500	2585.28500
तृतीय चरण (2017-18)	634.70750	325.60375	309.10375	43.03000	1312.44500	43.03000	1355.47500
चत्तुर्थ चरण (2018-19)	44.20000	22.10000	22.10000	45.53000	133.93000	45.53000	179.46000
पंचम चरण (2019-20)	44.20000	22.10000	22.10000	45.25000	133.65000	45.25000	178.90000
डी॰पी॰आर॰ शुल्क	-		=	1.24000	1.24000	1.24000	2.48000
कुल योग :	2633.62000	1363.68500	1269.93500	219.80500	5487.04500	219.80500	5706.85000

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) शुल्क ₹ 2.48 लाख रुपये का भुगतान सलाहकार संस्था को पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 131 दिनांक 24.03.2011 द्वारा किया जा चुका है।

- 6. औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के लिए चरणवार स्वीकृत राशि के अनुरूप किसी वित्तीय वर्ष में राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व चरण की राशि की निकासी की जा सकेगी। निगम द्वारा पाँचों जिलों की योजना की स्वीकृति पाँच वर्ष के लिए प्रदान की गई है अतएव निकासी की गई राशि का उपयोग पूरी परियोजना अवधि तक की जा सकेगी।
- 7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले निदेशों के अनुरुप औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के परियोजना अंतर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित राशि का अंतःक्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय मद परिवर्त्तन स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप शीर्ष परिवर्त्तन किये बिना किया जा सकेगा।
- 8.(क) निगम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त ऋण की अवधि निगम के प्रावधानुसार 8 वर्ष निर्धारित है। मार्जिन मनी / हिस्सा पूंजी देने के लिए ऋण पर कोई ऋण स्थगन (Moratorium) नहीं दिया जाएगा। शेष ऋण राशि हेतु मूलधन की वापसी पर 3 वर्षों का ऋण स्थगन होगा, ऋण स्थगन अवधि ऋण की प्रथम किस्त की निकासी की मानित तिथि से मानी जाएगी। निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले ऋण पर निधियों की वास्तविक विमुक्ति के समय प्रचलित ब्याज दरें लागू होगी। वर्त्तमान में प्रभावी ब्याज दर 11.45% है, यदि किस्त का भुगतान देय तिथि को अथवा उससे पहले किया जाता है तो प्रभावी (Effective) ब्याज दर लागू होगी। यदि किस्त का भुगतान देय तिथि को अथवा उससे पूर्व नहीं किया जाएगा तो सामान्य (Normal) ब्याज दर लागू होगी, जो प्रभावी (Effective) ब्याज दर से 1% अधिक है। इसके अतिरिक्त किस्तों के भुगतान में विलंब होने के मामले में नहीं चुकाई गई किस्तों (Defaulted Amount) पर दंडात्मक (Penal) ब्याज दर जो कि सामान्य (Normal) ब्याज दर से 2.5% अधिक है, विलंबित अवधि में देय होगी।
- (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि पर साधारण ब्याज दर पर सूद की गणना की जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त 75% ऋण एवं 25% अनुदान की गणना के आधार पर वर्त्तमान समय में प्रभावी ब्याज की दर (Effective Rate of Interest) पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
- (ग) निगम को ऋण किस्त तथा ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी तक कर देना है। ब्याज दर निगम के संशोधनों से प्रभावित होगा। अन्य शर्त्ते निगम के स्वीकृति पत्र एवं अनुबंध के अनुसार होंगे।

यह ब्याज दर समय-समय पर निगम द्वारा इसमें किये जाने वाले संशोधनों से प्रभावित होगा।

- 9. आई॰सी॰डी॰पी॰, औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ योजनान्तर्गत समितियों को उपलब्ध कराई गई चक्रीय पूंजी पर समितियों से कोई सूद नहीं लिया जायेगा एवं इसकी वापसी योजना प्रारंभ होने के अगले वर्ष से 10 वर्षों में 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में की जा सकेगी। चक्रीय पुंजी की उक्त राशि की वापसी से एक चक्रीय निधि (Revolving Fund) का सुजन समग्र निधि (Corpus Fund) के रुप में किया जायेगा। इस निधि की राशि का उपयोग जिले के अंतर्गत सहकारी समितियों में निर्मित आधारभूत संरचनाओं के रख–रखाव तथा नई अधिसंरचनाओं के निर्माण हेत् किया जाएगा। चक्रीय पूंजी से सृजित निधि (राशि) संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया एवं पूर्णियाँ तथा दरभंगा जिला हेत् राज्य सहकारी बैंक की दरभंगा शाखा में इस निधि को रखा जायेगा तथा इसका अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा। इस निधि के राशि के उपयोग हेत् जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटि गठित होगी, जिसके सदस्य संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक तथा जिले में पदस्थापित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ होंगे। परियोजना में पदस्थापित विकास पदाधिकारी वसूली हेतू व्यक्तिगत प्रयास करेंगे। लाभान्वित समितियों, चक्रीय पूंजी किस्त राशि की वसूली की स्थिति में आये, इसके लिये नोडल पदाधिकारी, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, समितियों के व्यवसाय विकास को सुदृढ करने हेतू कार्रवाई तथा सभा, सेमिनार, संगोष्ठी का आयोजन कर समितियों को प्रोत्साहित करेंगे। निबंधक, सहयोग समितियाँ परियोजनान्तर्गत चयनित समितियों को अंकेक्षण नियमित रूप से कराया जाना सनिश्चित करेंगे तथा परियोजना कार्यान्वयन में निगम द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 10. परियोजनान्तर्गत लाभान्वित समितियों, पैक्सों, व्यापार मंडलों, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष से वसूल की गई चक्रीय पूंजी की राशि औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया एवं पूर्णियाँ जिलों के केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि॰ तथा दरभंगा जिला हेतु राज्य सहकारी बैंक की दरभंगा शाखा में जमा की जायेगी तथा उसका समेकित प्रतिवेदन राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सहकारिता को ससमय भेजा जायेगा।
- 11. जिलों में परियोजना प्रारम्भ करने हेतु राशि निकासी के पूर्व परियोजना कार्यान्वयन दल (पी.आई.टी.) में कार्मिकों की नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति / पदस्थापन की प्रक्रिया निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित "कार्मिक चयन समिति" द्वारा कर ली जायगी।
- 12. संबंधित महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, परियोजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर एक कार्यालय गठित करेंगे। महाप्रबंधक के अधीन एक परियोजना कार्यान्वयन दल (P.I.T.) कार्यरत होगा, जो परियोजना कार्यों का संचालन करेगा।

- 13. परियोजना के अंतिम तीन माह में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी / दल परियोजना समापन प्रतिवेदन निगम द्वारा निर्गत प्रपत्र में तैयार कर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य अनुश्रवण कोषांग, आई॰सी॰डी॰पी॰, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।
- 14. परियोजना का पूर्णता प्रतिवेदन तैयार करते समय यदि कोई परियोजना राशि अनुपूरक रह जाती है या एजेंसी के पास बची रह जाती है तो उसे ट्रेजरी चालान द्वारा राज्य कोषागार में जमा कर उसकी सूचना, चालान की प्रति के साथ विभाग को प्रेषित की जायेगी।
- 15. परियोजना की समाप्ति के समय परियोजना के सभी Records(चक्रीय पूंजी /एल.डी./यू.डी. के अतिरिक्त अनुदान, एल.डी./यू.डी. अनुदान तथा राज्यांश अनुदान सिंहत) अवशेष राशि, परियोजना कार्यालय के उपष्कर (Assests) परियोजना वाहन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को संबंधित महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी. को हस्तांतरित करेंगे। संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि. परियोजना पूर्ण होने के उपरांत समितियों के बकाया चक्रीय पूंजी की वसूली सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए वे जवाबदेह होगें। वसूली की सूचना निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के माध्यम से प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 16. परियोजना समापन के उपरांत परियोजना अंतर्गत आच्छादित समितियों में यदि कोई कार्य अवशेष रह जाता है और उस कार्य को पूर्ण कराने हेतु समिति के खाता में परियोजनान्तर्गत प्राप्त अवशेष राशि रहती है तो उस कार्य को पूर्ण कराने हेतु संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को समिति के खाता से राशि निकासी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
- 17. परियोजना कार्यान्वयन में निगम के प्रावधानों, निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा, जो निगम का परियोजना स्वीकृति पत्र एवं उसके अनुलग्नकों में दर्शित है।
- 18. परियोजना अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति :— परियोजनान्तर्गत समितियों के चयन हेतु NCDC द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु उन्हीं समितियों का चयन किया जाना है, जो अच्छा कार्य कर रही है, जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो, जिसमें विकास की संभावना हो तथा जो परियोजनान्तर्गत दिये गये चक्रीय पूंजी भार को सहन कर सके। प्रत्येक चयनित समिति में निर्धारित प्रबंध समिति का रहना अनिवार्य है। समितियों का चयन करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतू NCDC द्वारा निर्धारित शर्तों का भी चयन किया जाएगा।

समेकित सहकारी विकास परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु पर यह है कि परियोजना में सही समितियों (Viable Socities) का चयन हो। परियोजना के अंतर्गत समितियों का चयन जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के पश्चात् परियोजनानुरूप महाप्रबंधक द्वारा लाभान्वित समितियों को राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। इस मद में राज्य सरकार से प्राप्त राशि संबंधित महाप्रबंधक द्वारा संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या निबंधक, सहयोग समितियाँ के निर्देशानुसार अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक / राज्य सहकारी बैंक में खाता खोलकर जमा की जायेगी एवं महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से राशि को निकासी की जायेगी। संबंधित महाप्रबंधक ही व्ययन पदाधिकारी होगे। महाप्रबंधक PIT में कार्यरत कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। इन कर्मियों के वेतनादि का भुगतान उन्हीं के हस्ताक्षर से होगा।

- 19. गोदाम निर्माण :- जिला स्तरीय समन्वय सिमित द्वारा स्वीकृति के पश्चात् NCDC के उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में लाभान्वित सिमितियों द्वारा गोदाम निर्माण कार्य कराया जाएगा। गोदाम निर्माण हेतु लाभान्वित पैक्सों को हस्तांतिरित राशि के व्यय, लेखा संधारण एवं उपयोगिता की जिम्मेवारी पैक्स के अध्यक्ष / प्रबंधक की होगी। गोदाम निर्माण की तकनीकी पर्यवेक्षण की पी॰आई॰टी॰ / जिला स्तरीय समन्वय सिमित द्वारा प्रतिनियुक्त अभियंता द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक जिले में पी॰डब्लू॰डी॰ द्वारा निर्गत Schedule of rate के आधार पर प्रतिनियुक्त अभियंता प्राक्कलन तैयार करेंगे। NCDC द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप हीं गोदाम निर्माण का भुगतान होगा। अंतिम विपत्र संबंधित जिलों के जिल स्तरीय समन्वय सिमित द्वारा नामित साक्षम अभियंता द्वारा पारित किया जायेगा।
- 20. सिमितियों का चयन तथा उप परियोजना की स्वीकृति :— परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित होनेवाली सिमितियों का चयन तथा उप परियोजना की स्वीकृति PIT की अनुशंसा के उपरांत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय सिमित द्वारा किया जायेगा।
- 21. आच्छादित समितियों से संबंधित आस्तियों (Assests) का क्रय :- समेकित सहकारी विकास परियोजना से संबंधित बुनकर, लूम, पंपसेट, चावल मिल आदि का क्रय समितियों NCDC के स्वीकृत्यादेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार PIT की देख-रेख में स्वयं करेंगी। क्रय किये गये अस्तियों (Assests) के गुणवत्ता के लिये समिति तथा महाप्रबंधक उत्तरदायी होंगे।
- 22. पैक्सों को फर्निचर, फिक्सचर, सेफ भॉल्ट एवं काउन्टर इत्यादि देने के संबंध में :- PIA की स्वीकृति के पश्चात् राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के स्वीकृत्यादेश के अनुरूप फर्नीचर, फिक्सचर, सेफ भॉल्ट एवं काउन्टर इत्यादि हेतु प्रावधानित राशि संबंधित समितियों को हस्तांतरित की जायेगी। सभी उपस्कर प्रमाणिक कंपनी के होंगे तथा अधिकृत विक्रेता से ही खरीद की जायेगी। समितियाँ अपना उपस्कर स्वयं PIT के मार्ग–दर्शन में खरीद करेंगी। उपस्करों की गुणवत्ता की देख–रेख महाप्रबंधक तथा विकास पदाधिकारी करेंगे।

- 23. PIT का अंकेक्षण :— राज्य अनुश्रवण कोषांग तथा PIT का अंकेक्षण निबंधक, सहयोग सिमतियाँ, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वर्षान्त के तीन माह के अंदर उनके द्वारा निबंधक, सहयोग सिमतियाँ को उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित किया जायेगा। संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग सिमतियाँ तथा राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी परियोजनान्तर्गत चयनित सिमतियों का अद्यतन अंकेक्षण हेतु संबंधित जिलों के जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यों की सिमका करेंगे।
- 24. राज्य अनुश्रवण कोषांग का कार्य :— परियोजना का अनुश्रवण/मार्गदर्शन के लिए पूर्व से निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन गठित राज्य अनुश्रवण कोषांग में अन्य कर्मियों के अतिरिक्त राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी भी पदस्थापित हैं। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी सभी जिलों के कार्यों की समीक्षा एवं मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं परियोजना को विमुक्त राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा इससे विभाग एवं NCDC को अवगत कराना इनका मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य अनुश्रवण कोषांग द्वारा प्रत्येक माह बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेना, परियोजना के कार्यों की समीक्षा, समितियों का परिदर्शन एवं सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों का संप्रेषण इनके महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी 6 माह में एक बार या आवश्यकता अनुरूप राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन विभागीय सचिव/प्रधान सचिव की सुविधानुसार करेंगे। इस राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक विभागीय सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में संपन्न होगी। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी जिला स्तर पर पदस्थापित महाप्रबंधकों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का लेखन करेंगे। परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- 25. राशि के उपयोग की जिम्मेवारी :— परियोजनान्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेवारी महाप्रबंधक की होगी। उनका दायित्व होगा की प्राप्त वित्तीय सहायता समय पर लाभान्वित समितियों को प्राप्त हो, इसके लिए वे बैंक स्थित परियोजना के खाता का संचालन करेंगे।
- **26.** जिला स्तरीय समन्वय समिति :— समेकित सहकारी विकास परियोजना की मोनिटरिंग, समीक्षा, निर्देशन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति निम्न प्रकार गठित की जाती है :—

(i)	जिला पदाधिकारी संबंधित जिला	–अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त संबंधित जिला	–सदस्य
(iii)	संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि. के अध्यक्ष	–सदस्य
(iv)	महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰ संबंधित जिला	–सदस्य सचिव
(v)	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि॰ संबंधित जिला	–सदस्य
(vi)	जिला सहकारिता पदाधिकारी संबंधित जिला	–सदस्य
(vii)	जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित जिला	–सदस्य
(viii)	जिला पशुपालन पदाधिकारी संबंधित जिला	–सदस्य
(ix)	जिला उद्योग पदाधिकारी संबंधित जिला	–सदस्य
(x)	जिला मत्स्य पदाधिकारी संबंधित जिला	–सदस्य
(xi)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक कार्यपालक अभियंता संबंधित जिला	–सदस्य
(xii)	परियोजना कार्यान्वयन दल (PIT) में पदस्थापित अभियंता	–सदस्य
(xiii)	राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी / सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰	–सदस्य
(xiv)	मुख्य / क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, पटना	–सदस्य

उपर्युक्त गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) समेकित सहकारी विकास परियोजना में निगम के प्रावधानुसार कार्यान्वयन प्रगति परियोजना राशि का निर्धारित अवधि में उपयोग, चक्रीय पूंजी राशि की समितियों से वसूली की समीक्षा अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी, मार्गदर्शन एवं निर्देशन करेगी तथा समिति की बैठक की कार्यवाही नोडल पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰ तथा प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं NCDC को भेजेगी।

जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक प्रत्येक माह तथा आवश्यकतानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर होगी।

27. राज्य स्तरीय समन्वय समिति :— राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समन्वय समिति" परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी तथा प्रगति की नियमित समीक्षा/मोनिटरिंग एवं निदेशन करेगी। इस समिति के सदस्य सचिव, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समिति अध्यक्ष, प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग से पूर्व समय निर्धारित कर प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रत्येक छः माह पर या आवश्यकता पड़ने पर, कभी भी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत करेंगे तथा समीक्षा हेतु प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य सुझाव प्रस्तुत करेंगे। परियोजनान्तर्गत प्रावधानित राशि का अगर मद परिवर्त्तन, इकाई की संख्या/इकाई लागत आदि में परिवर्त्तन अनिवार्य हो तो इस हेत राज्य स्तरीय समन्वय समिति की

सहमति प्राप्त की जायेगी तदनुपरांत NCDC की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत महाप्रबंधक को संबंधित परिवर्त्तन को कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया जायेगा। नीतिगत मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति सक्षम होगी। राज्य स्तरीय समन्वय समिति निम्न प्रकार गठित होगी :--

(i)	प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना	–अध्यक्ष
(ii)	वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	–सदस्य
(iii)	निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना	–सदस्य
(iv)	निदेशक, मत्स्य विभाग, बिहार, पटना	–सदस्य
(v)	निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना	–सदस्य
(vi)	निदेशक, गव्य, बिहार, पटना	-सदस्य
(vii)	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना	-सदस्य
(viii)	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना	-सदस्य
(ix)	निदेशक, उद्योग, बिहार, पटना	-सदस्य
(x)	निदेशक (ICDP) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	-सदस्य
(xi)	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त	-सदस्य
(xii)	राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰	–सदस्य सचिव
(xiii)	मुख्य / क्षेत्रीय निदेशक, एन॰सी॰डी॰सी॰, पटना	-सदस्य
(xiv)	संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी	–सदस्य
(xv)	संबंधित जिला के महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना	–सदस्य
(xvi)	संबंधित जिला के प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि॰	-सदस्य
	ν οο ο ' σσον ' ο ' ο ' ο ' ο ' ο ' ο ' ο ' ο ' ο '	O 11

28. **कार्मिक चयन समिति** :— निगम के प्रावधानानुसार ICDP के कार्यान्वयन के लिए गठित होने वाली परियोजना कार्यान्वयन दल (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) के अन्तर्गत कार्मिकों की नियुक्ति हेतु चयन / प्रतिनियुक्ति / पदस्थापना के लिए निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (NODAL OFFICER) की अध्यक्षता में "कार्मिक चयन समिति" का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

- (i)
 निबंधक, सहयोग सिनितयाँ, बिहार, पटना
 —अध्यक्ष

 (ii)
 राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी.
 —सदस्य सिचव
- (iii) प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता द्वारा मनोनित प्रतिनिधि —सदस्य अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
- (iv) मुख्य निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.डी.सी., पटना —सदस्य कार्मिकों को चयन समिति, NCDC के प्रावधानों तथा राज्य सरकार की स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार करेगी, जो निम्निलखित है :-
 - (i) उपर्यक्त पदों पर बहाली केन्द्रीय सहकारी अधिकोष / राज्य सरकार / राज्य सरकार की संस्था तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त कार्मिक चयन सिनित के चयनोपरांत की जायेगी। उक्त प्रक्रिया से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर व्यापक एडवरटाइजमेंट कर कार्मिकों का चयन किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य भत्ते राज्य सरकार के प्रावधानानुसार ही देय होंगे।
 - (ii) उपर्यक्त पदों पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति में राज्य सरकार एवं राज्य सरकार की संस्था के कार्मिकों हेत् उम्र सीमा का बंधेज नहीं रहेगा।
 - (iii) कार्मिकों की नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं उम्र सीमा के शिथिलीकरण का अधिकार प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को होगा।
 - (iv) एक्सेप्सनल केस में अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। विशेष परिस्थिति में कार्मिक चयन समिति अधिकतम उम्र सीमा की छूट को बढ़ा सकती है।
 - (v) औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के परियोजना के सभी पदों पर कार्यरत पदाधिकारी / कर्मी के लिए सामान्यतः राज्य सरकार की शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान / अनुभव आदि लागू होंगे।
 - (vi) औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के परियोजना कार्यान्वयन दल में पदस्थापित पदाधिकारी / कार्मिकों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार तथा एन सी डी सी द्वारा (50:50) परियोजना को स्थापना आदि व्यय हेतु दी गयी अनुदान राशि से वहन किया जायेगा।
 - (vii) औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के परियोजना कार्यान्वयन दल में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों पर अन्य शर्ते राज्य सरकार की ही लागू होगी।
 - (viii) औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों के परियोजना कार्यान्वयन टीम के लिए पदाधिकारी/कार्मिक का चयन एवं नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन/वेतन भत्तों का निर्धारण—

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित—एक समिति की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰ द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(ख) राज्य अनुश्रवण कोषांग, आई॰सी॰डी॰पी॰ — समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं के जिलों में परियोजना कार्यान्वयन एवं प्रगति के अनुश्रवण ∕ मार्गदर्शन के लिए पूर्व से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के अधीन गठित है, जो इस प्रस्तावित आई॰सी॰डी॰पी॰, औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिला के परियोजना कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी।

राज्य अनुश्रवण कोषांग, आई॰सी॰डी॰पी॰, बिहार, पटना हेतु पदों की संरचना निम्नवत है :--

- 1. राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी आई॰सी॰डी॰पी॰ 1
- 2. सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी 2
- 3. कार्यालय सहायक / एकाउन्टेंट 2
- 4. डाटा इंट्री आपरेटर 1
- 5. स्टोनो टाइपिस्ट 1
- 6. वाहन चालक 1
- 7. पिउन / सुरक्षा गार्ड 1

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली एवं पटना / महालेखाकार, बिहार सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों / कार्यालयों को सूचित किया जाय।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) ४९१-५७१+१०-डी०टी०॥।

Website: http://egazette.bih.nic.in